भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *155
उत्तर देने की तारीख 10 दिसंबर, 2025

दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी

***155. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहानः**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24 के अंतर्गत रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर के कई गांवों और दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की कमी के कारण नागरिकों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासनिक कार्यों में बाधा आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराने और वहां मोबाइल टावर लगाने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त क्षेत्रों में नेटवर्क सुविधा प्रदान करने हेतु अनुमानित समय-सीमा क्या है?

उत्तर
संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी के संबंध में दिनांक 10 दिसंबर, 2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *155 के भाग (क) से (ग) के संबंध में लोक सभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण

(क) नवंबर 2025 तक, मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में 2,450 गांवों में से 2,428 गांव मोबाइल कनेक्टिविटी से कवर किए गए हैं।

(ख) से (ग) सेवा से वंचित आबादी वाले गांवों के लिए मोबाइल कवरेज तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा प्रदान की जाती है।

सरकार, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त इनपुट के आधार पर, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल कवरेज का आकलन करती है। सेवा से वंचित पाए गए गांवों का सर्वेक्षण उनकी मोबाइल कवरेज स्थिति की पुष्टि के लिए किया जाता है। इसके बाद, डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) द्वारा वित्त पोषित 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी स्कीमों के तहत सेवा से वंचित गांवों को कवरेज उपलब्ध कराया जाता है।

सरकार, डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के माध्यम से प्राप्त वित्तपोषण से देश के ग्रामीण, दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में 4जी मोबाइल टावरों की संस्थापना के माध्यम से दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार हेतु विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। नवंबर 2025 तक, डीबीएन द्वारा वित्तपोषित मोबाइल स्कीमों के अंतर्गत रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में 32 साइट चालू हो चुकी हैं, जिससे 41 गाँवों को मोबाइल कवरेज प्रदान की जा रही है।

******